विशेष आयात लाइसेंसों के अन्तर्गत सोने/चांदी के आयात के संबंध में उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :—

अप्रैल, 94 से 21-7-1994	सोना	7.014 टन
मई, 94 से जून, 94	चांदी	80 टन

(स्रोत : जी.ज.ई.पी.सी.)

(ख) रत्न और आभूषणों के निर्यातक सोने एवं चांदी का आयात व्याप्त अन्तर्राष्ट्रीय दरों पर करते हैं। सोने/चांदी का निर्यात मूल रूप में नहीं किया जाता। फिर भी, पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सोने के आभूषणों तथा सोना-भिन्न के आभूषणों का निर्यात इस प्रकार है :—

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	सोने के आभूषण	सोने भिन्न के आभूषण
1993-94	365.57	8.47
1994-95 (अप्रैल से मई, 1994)	57.07	0.75

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि सरकार सोने और चांदी का व्यापार नहीं करती।

सिक्कों का निर्माण

1002. मौलाना अबेदुल्ला खान आजमी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न सिक्कों के निर्माण पर कितनी-कितनी लागत आती है ;

(ख) क्या सरकार ने पांच, दस और बीस पैसे के सिक्कों का निर्माण बंद कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि देश के कई भागों में 25 पैसे से कम मूल्य के सिक्कों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) टकसाल में विभिन्न मूल्यवर्गों के सिक्कों के ढालने पर लगाई जा रही लागत नीचे दी गई है:—

मूल्य वर्ग	कुल लागत (प्रतिशतक)
5 रुपये (कूपरी निकल)	2.79 रुपये
2 रुपये (कूपरी निकल)	1.60 रुपये
1 रुपये (स्टेनलेस स्टील)	1.00 रुपये
50 पैसे (स्टेनलेस स्टील)	0.64 रुपये
25 पैसे (स्टेनलेस स्टील)	0.48 रुपये
20 पैसे (अल्यूमीनियम मग्नीशियम)	0.36 रुपये
10 पैसे (स्टेनलैस स्टील)	0.18 पये
5 पैसे (अल्यूमीनियम मैग्नीशियम)	0.21 पये

(घ) और (घ) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) ऐसे सिक्कों को स्वीकार न करने का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है ।

Listing Fees by Guwahati Stock Exchange

1003. SHRI JALALUDIN ANSARI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Guwahati Stock Exchange (GSE) has to realise huge listing fees from various companies listed by it; if so, the names of such companies along with the details of the respective amounts to be realised from each such company at present and the details of steps taken to realise the same;

(b) whether GSE has been following the system of accounting of listing fees on accrual basis and not on actual basis; if so, the reasons therefor;

(c) whether the practice followed by GSE has resulted in gross anomaly in calculating the surplus of income over expenditure and presently such surplus as shown by following this practise is almost fictitious; if so, what remedical steps are proposed in this regard;

(d) the names of companies listed by GSE during last three years and in the current year so far; and

(e) the details of specific steps taken by the council of management of GSE during its current tenure to increase the number of listed companies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) The Guwahati Stock Exchange has indicated that the total outstanding listing fees yet to be realised by the Exchange is Rs. 7,40,737. The names of the companies and corporations and the amounts of listing fees to be realised by the Stock Exchange are given in Statement-I. (See below). In order to realise the outstanding listing fees, the Stock Exchange has been regularly corresponding with the concerned companies/corporations and has also issued notices for delisting of securities in some cases.

(b) Yes, Sir. The Guwahati Stock Exchange is a company registered under the Companies Act, 1956 and, accordingly, is required to maintain its books of account on accrual basis in terms of the provisions of Section 209(3) (b) of the Act.

(c) According to the Stock Exchange, the practice of accounting of listing fees on accrual basis has not created any anomaly in its financial position, particularly since there has been some recovery of the receivables. Therefore, the question of taking remedial steps does not arise.

(d) The names of the companies listed by the Exchange during the last three years and in the current year so far are given in Statement-II. (See below).

(e) The Stock Exchange has been communicating with various companies to get their securities listed on the Exchange.